International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 14-08-2021; Accepted: 29-08-2021; Published: 14-09-2021
Volume 3, Issue 2, 2021, Page No. 27-30

भारत–अफगानिस्तान का राजनीतिक संबंध अतीत से वर्तमान

डॉ. रमेश प्रसाद कोल
सहायक प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग, शासकीय रणविजय प्रताप सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
अफगानिस्तान और भारत एक दूसरे के पड़ोस में स्थित दो प्रमुख दक्षिण एशियाई देश हैं। दोनों दक्षिण एशियाई क्षेत्रिय सहयोग संगठन (दक्षेस) के भी सदस्य हैं। दोनों देशों के बीच प्राचीन काल से ही गहरे संबंध रहे हैं। 21वीं सदी में तालिबान के पतन के बाद दोनों देशों के संबंध फिर से काफी मजबूत हो गए हैं। भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई प्रकार के विकासीय समझौते किये हैं। भारत और अफगानिस्तान दोनो एक दूसरे का हमेशा अंतरराष्ट्रीय मंच पर समर्थन करते हैं। द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी करार 2011 के तत्वावधान में गठित भारत और अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक भागीदारी परिषद की द्वितीय बैठक 11 सितम्बर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री रब्बानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भी भेंट की। प्रधानमंत्री और भारत की विदेश मंत्री ने बल दिया कि दोनों देशों के बीच समय की कसौटी पर खरे उतरे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, तथा उन्होंने एक एकीकृत, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध और बहुलवादी अफगानिस्तान के निर्माण में भारत के निरंतर सहयोग को दोहराया। राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों, व्यापार, वाणिज्य और निवेश, विकास सहयोग, तथा मानव संसाधन विकास, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रो में चार संयुक्त कार्यकारी समूहों के परिणामों की समीक्षा की गई और उनका सकारात्मक मूल्यांकन किया गया। इस बात पर आम सहमति बढ़ती जा रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने विफल युद्धों में ही संलग्न बने रहने के बजाय अब चीन के साथ उभरती भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा के लिये स्वयं को तत्काल तैयार करना चाहिये। तालिबान को पराजित करना और अफगानिस्तान का राष्ट्र–निर्माण अमेरिका की नव–रूढ़िवादी विचारधारा लोकतंत्र को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप का अंग रहा था, जो स्पष्ट रूप से विफल रहा है। हालाँकि अमेरिका भले ही अफगान सरकार का साथ छोड़ दे और इससे बाहर निकल आए किंतु भारत यह जोखिम नहीं उठा सकता। उसे न केवल अपने निवेश की रक्षा करनी है बल्कि अफगानिस्तान को भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के लिये एक और सुरक्षित आश्रय बनने से रोकना है। इसके साथ ही भारत को काबुल के ऊपर पाकिस्तान के प्रभाव में वृद्धि पर भी संतुलित नियंत्रण कायम रखना है।

मूलशब्दः भारत–अफगानिस्तान राजनीतिक संबंध अतीत, वर्तमान

प्रस्तावना
भारत–अफगानिस्तान संबंध भारत और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों को संदर्भित करता है, जिसने 2001 और 2021 के बीच अधिकांश अफगानिस्तान पर शासन किया। वे ऐतिहासिक पड़ोसी थे, बॉलीवुड और क्रिकेट के माध्यम से सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। 1980 के दशक में सोवियत समर्थित लोकतांत्रिक गणराज्य अफगानिस्तान को मान्यता देने वाला भारत गणराज्य एकमात्र दक्षिण एशियाई देश था, हालांकि 1990 के दशक के अफगान गृहयुद्ध और तालिबान सरकार के दौरान संबंध कम हो गए थे। भारत ने तालिबान को उखाड़ फेंकने में सहायता की और अफगानिस्तान के पूर्व इस्लामी गणराज्य को मानवीय और पुनर्निर्माण सहायता का सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रदाता बन गया। अफगानिस्तान में भारत के पुनर्निर्माण प्रयासों के हिस्से के रूप में भारतीय विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान को बदनाम करने और विद्रोहियों को प्रशिक्षित करने और समर्थन देने के लिए काम कर रही है। एक दावा जिसे भारत ने दृढ़ता से खारिज कर दिया। अप्रैल 2017 में भारत में अफगानिस्तान के राजदूत शैदा मोहम्मद अब्दाली ने बताया कि भारत अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा क्षेत्रीय दाता है, और वैश्विक स्तर पर पांचवां सबसे बड़ा दाता है, जिसकी सहायता में 3 अरब डॉलर से अधिक है। भारत ने 200 से अधिक सार्वजनिक और निजी स्कूलों का निर्माण किया है, 1,000 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रायोजित की हैं। 16,000 से अधिक अफगान छात्रों की मेजबानी करता है। अफगानिस्तान और भारत के बीच संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के साथ 2011 में एक बड़ा बढ़ावा मिला, 1979 के सोवियत आक्रमण के बाद अफगानिस्तान का जून 2021 में कतर के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा अफगान तालिबान पर भारत की स्थिति में एक बड़े बदलाव की सूचना दी गई, जिसमें खुलासा किया गया कि तालिबान के नेतृत्व से मिलने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल चुपचाप दोहा गया था। यह एक प्रमुख बदलाव है जो 2021 की पहली छमाही में बनने में कई सप्ताह था, और इसमें भारत और तालिबान के बीच कतरी मध्यस्थता शामिल होने की संभावना थी।

भारत–अफगानिस्तान का राजनीतिक संबंध
29 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर कब्जा करने के पश्चात् तालिबान के वरिष्ठ नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई ने भारत को क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश बताते हुए कहा है कि तालिबान भारत के साथ अफगानिस्तान के व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना चाहता है। स्तानिकजई ने पश्तो भाषा में जारी एक वीडियो संबोधन में कहा कि काबुल में सरकार बनाने के लिए विभिन्न समूहों और राजनीतिक दलों के साथ विचार–विमर्श चल रहा है, जिसमें ''विभिन्न क्षेत्रों'' के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा।

स्तानिकजई ने शनिवार को कहा, ''हम भारत के साथ अपने व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। स्तानिकजई ने पश्तो भाषा में जारी एक वीडियो संबोधन में कहा कि काबुल में सरकार बनाने के लिए विभिन्न समूहों और राजनीतिक दलों के साथ विचार–विमर्श चल रहा है, जिसमें ''विभिन्न क्षेत्रों'' के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा।

भारत और पाकिस्तान दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में आतंक और हिंसा की घटनाओं पर गंभीर चिंता दर्शायी जिसके परिणामस्वरूप अनेक मासूम लोगों की जानें गईं। यह देखते हुए कि आतंकवाद किसी क्षेत्र और उसके आस–पास के क्षेत्रों की शांति, स्थायित्व और प्रगति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उन्होंने अफगानिस्तान के विरुद्ध आतंकवादियों को सहायता, राष्ट्र तथा प्रायोजन, सुरक्षित स्थानों और उनके अभ्यारण्यों के सभी स्वरूपों को समाप्त करने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने पर सहमति हुई। भारत ने आतंकवाद, संगठित अपराध, स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार और धन–शोधन के संकट के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा सेवाओं के लिए और अधिक सहायता प्रदान करने पर सहमति दी। भारतीय पक्ष ने एक अफगान–संचालित और अफगान–स्वामित्व वाली शांति और समाधान प्रक्रिया के लिए अपने सहयोग को दोहराया। यह सहमति हुई कि अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की सफलता के लिए हिंसा की तत्काल समाप्ति हेतु ठोस, अर्थपूर्ण और सत्यापनीय कदम उठाए जाएंगे।

भारत और अफगानिस्तान दोनों पक्षों ने जून, 2017 में नई दिल्ली के साथ काबुल और कंधार के बीच एयर कार्गो कॉरीडोर की स्थापना का स्वागत किया गया। इसे अफगानिस्तान और भारत के अन्य देशों को शामिल करने के लिए तथा दोनों देशों के बीच कार्गो उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए इसका विस्तार करने पर सहमति प्रदान की गई। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए संयोजनता तथा मुक्त और निर्बाध परिवहन एवं पारेषण पहुंच के महत्व की पुनरू पुष्टि करते हुए दोनों पक्ष मई, 2016 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारेषण कॉरीडोर की स्थापना के लिए द्विपक्षीय करार के अंतर्गत ईरान में चार बहार पोर्ट को शीघ्र प्रचालन में लाने के लिए कार्य करने पर सहमत हुए। इस संदर्भ में, दोनों पक्ष संयुक्त निवेशों का अन्वेषण करने पर सहमत हुए। अफगान पक्ष ने भारत से अफगानिस्तान को बरास्ता चारबहार पोर्ट 1,70,000 मीट्रिक टन की गेहूँ की पोतों द्वारा आपूर्ति शीघ्र आरंभ करने का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय पारेषण और व्यापार करार को अधिक अंतर्वेशी और व्यापक बनाने की आवश्यकता पर बल प्रदान किया जिसके लिए दक्षिण एशिया को मध्य एशिया के साथ जोड़ने के लिए इसका विस्तार उत्तर और दक्षिण, दोनों दिशाओं की ओर किया जाएगा। उन्होंने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन की ओर संयुक्त प्रयास करने के महत्व पर भी बल प्रदान किया जो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच संयोजनता और व्यापारिक सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। व्यापार और निवेश की पर्याप्त संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने के लिए उत्पादों और उपायों की पहचान करने पर भी सहमति हुई जिसमें रत्नों, भेषजिक सामग्रियों और कृषि–उत्पादों का प्रत्यक्ष व्यापार भी शामिल है। इस संदर्भ में, गुणवत्ता आश्वासन और मानकीकरण, संभार–तंत्र और प्रशीतित भण्डारणों के निर्माण, मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए विनिर्माण क्षमता के सृजन, बैंकिंग और वित्त, क्रेडिट और बीमा की पहचान की गई। क्रेता–विक्रेता कार्यक्रम संचालित करने तथा व्यापार चेम्बरों और व्यापारियों के बीच अधिक संपर्क स्थापित करने पर सहमति हुई। इस संदर्भ में, भारत–अफगानिस्तान व्यापार और निवेश प्रदर्शनी जो 27–29 सितम्बर, 2017 तक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है, व्यापारिक समुदायों को एक–साथ लेकर आएगी। अफगान राष्ट्रिकों के लिए भारत द्वारा किए गए वीजा उपायों के उदारीकरण, जिसमें 5 वर्ष तक अनेक बार प्रवेश करने के लिए व्यापार वीजा प्रदान करने का निर्णय भी शामिल है, का एक ऐसे उपाय के रूप में स्वागत किया गया जो द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करेगा। अफगानिस्तान के लोग पिछले काफी समय से पड़ोसी देश उज्बेकिस्तान की तुलना में भारतीय खाद्य पदार्थों को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। उन्हें इसकी गुणवत्ता और कीमत पर अधिक भरोसा है। नई दिल्ली जयपुर के मैदा एक्सपोर्टर इंद्रपाल सिंह पिछले महीने काफी खुश थे। उन्हें अफगानिस्तान से 5,000 मीट्रिक टन मैदा भेजने का आर्डर मिला था और यह एक बार का ट्रांजैक्शन नहीं था। अफगानिस्तान के कारोबारियों की तरफ से यह हर महीने मंगाया जाने वाला सौदा था। अफगानिस्तान के लोग पिछले काफी समय से पड़ोसी देश उज्बेकिस्तान की तुलना में भारतीय खाद्य पदार्थों को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। उन्हें इसकी गुणवत्ता और कीमत पर अधिक भरोसा है।

भारत से कार्गो पर रोक

इस साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान में बहुत सी चीजें बदल गई है। अफगानिस्तान का चरमपंथी संगठन तालिबान काबुल में घुस गया है, और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही इलाके की जियो पॉलिटिक्स में काफी बदलाव आया। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के साथ ही भारत के कारोबारियों के हित प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि तालिबान भारत से होने वाले कारोबार में बाधा पैदा कर सकता है। छह महीने तक कारोबार प्रभावित कारोबारियों को आशंका है कि अगले 6 महीने तक तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान में कारोबार पर काफी असर पड़ सकता है। अगर बात सिर्फ एक कारोबारी की करें तो उन्हें 16 करोड़ हर महीने नुकसान होने की आशंका है। भारत के कारोबारी अब अफगानिस्तान की जगह वैकल्पिक इलाकों में कारोबार की संभावनाएं देख रहे हैं।

भारत के हित की रक्षा

अफगानिस्तान में सत्ता में बदलाव के बाद भारत अचानक अजीब सी मुश्किल में फंस गया है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के साथ ही नई दिल्ली कई अन्य मसलों पर भी चिंतित है। अफगानिस्तान में भारत के आर्थिक हितों की रक्षा और दोस्ती को कायम रखने की कवायद आदि बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। विश्लेषकों का कहना है कि तालिबान भारत द्वारा बनाए गए किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। तालिबान की कोशिश यह होगी कि भारत अफगानिस्तान में निवेश करना जारी रखे और वहां की स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करे। भारत को अपने हितों को देखते हुए और अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए अब फैसले लेने की जरूरत है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत को तालिबान से यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि अगर वे निवेश एवं अन्य मसलों पर भारत की मदद चाहते हैं तो उन्हें भारत की शर्त माननी पड़ेगी। विदेश मंत्रालय के आंकड़े यह बताते हैं कि भारत हर साल 3500 अफगान नागरिकों को भारत में पढ़ाई और ट्रेनिंग संबंधी मदद देता है। भारत के विभिन्न शहरों में करीब 15000 अफगान छात्र सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिस पर पढ़ाई करते हैं। अगर पीपल टू पीपल संबंधों के हिसाब से बात की जाए तो भारत ने नोएडा,

देहरादून और लखनऊ में अफगान क्रिकेटर को ग्राउंड भी दिए हुए हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडियन ग्राउंड को अपने घरेलू मैदान की तरह समझकर प्रैक्टिस करता है।

अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति

1990 के दशक में एक संक्षिप्त अवरोध को छोड़ दें तो अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं, जो वर्ष 1950 की मैत्री संधि से आगे बढ़े थे। भारतीय हितों और प्रभाव को तब धक्का लगा जब पाकिस्तान द्वारा समर्थित तालिबान ने वर्ष 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया। लेकिन वर्ष 2001 में अमेरिकी आक्रमण के बाद जैसे ही तालिबान को सत्ता से बेदखल किया गया, भारत ने पुनः अपनी खोई हुई स्थिति वापस प्राप्त कर ली। भारत ने तब से अफगानिस्तान में भारी निवेश और वित्तीय प्रतिबद्धताओं (3 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक) की पूर्ति की है और अफगान सरकार के साथ मज़बूत आर्थिक और रक्षा संबंध विकसित किये हैं। लेकिन अब एक बार फिर वह अनिश्चितता की स्थिति से गुज़र रहा है क्योंकि अमेरिकी सैन्य बल की वापसी ने अफगानिस्तान में शक्ति संतुलन को प्रभावी रूप से बदल दिया है और तालिबान अब यहाँ तेज़ी से अपनी क्षेत्रीय पकड़ मज़बूत कर रहा है।

अफगानिस्तान में भारत के पास उपलब्ध विकल्प तालिबान से संवाद भारत को निरंतर विकास सहायता या अन्य प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के बदले विद्रोहियों से सुरक्षा की गारंटी का अवसर प्रदान कर सकता है, साथ ही पाकिस्तान से तालिबान की स्वायत्तता की संभावना के अवसर तलाश किये जा सकते हैं। इस समय तालिबान से वार्ता करना अपरिहार्य नज़र आ रहा है। लेकिन भारत को पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठान और हक्कानी नेटवर्क (तालिबान के अंदर सक्रिय एक प्रमुख गुट) के बीच के गहरे संबंधों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिये। अमेरिका ने तालिबान से संघर्ष में इस पक्ष की अनदेखी की थी और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अफगान सरकार को विश्वास में लेना इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तालिबान को वार्ता में संलग्न कर इच्छित परिणाम पाने का भारत का कोई प्रयास वांछनीय परिणाम ही लाएगा। इसलिये भारत को अपने विकल्पों को व्यापक बनाए रखना चाहिये, जिसमें अफगान सरकार को विश्वास में लेना भी शामिल है। अपने हितों की रक्षा के लिये तालिबान से संवाद करते हुए भी भारत को अफगानिस्तान की वैध सरकार तथा सुरक्षा बलों की सहायता में वृद्धि करनी चाहिये और देश में दीर्घकालिक स्थिरता के लिये अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ सहयोग करना चाहिये। अफगान सैन्य बलों का समर्थनरू अफगान सेना में उच्च–प्रशिक्षित विशेष बलों सहित लगभग 200,000 युद्ध–अनुभवी सैनिक शामिल हैं। अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बल ही एकमात्र सैन्य बल है जो तालिबान के सामने डटकर खड़ा है। भारत को तत्काल अफगान बलों के प्रशिक्षण में सहयोग देना चाहिये और सैन्य हार्डवेयर, खुफिया सूचनाएँ तथा सैन्य एवं वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिये ताकि अफगान सेना शहरों की रक्षा करना जारी रख सके। भारत को अफगान सरकार का समर्थन करने के लिये अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भी समन्वय करना चाहिये क्योंकि अगर तालिबान के समक्ष सरकारी सेना कमज़ोर पड़ जाती है तो राजनीतिक समाधान की संभावनाएँ कम हो जाएँगी। क्षेत्रीय समाधान अफगानिस्तान में एक राजनीतिक समाधान हेतु भारत और तीन अन्य प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों– चीन, रूस तथा ईरान के बीच हितों का अभिसरण हो रहा है। इनमें से कोई भी देश अफगानिस्तान पर तालिबान के सैन्य नियंत्रण की इच्छा नहीं रखेगा क्योंकि इसका अर्थ होगा खंडित जातीय समीकरण वाले देश में एक अलग–थलग सुन्नी इस्लामवादी शासन की स्थापना। इसलिये इस विषय में समान विचारधारा वाले देशों से सहयोग की आवश्यकता है। लघु–आवधिक और दीर्घावधिक लक्ष्य भारत का तात्कालिक लक्ष्य अपने कर्मियों और निवेश की रक्षा एवं सुरक्षा होना चाहिये। भारत का दीर्घावधिक लक्ष्य संकट के राजनीतिक समाधान की तलाश होना चाहिये। इसमें से कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है, जब तक कि भारत अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर कार्य न करे।

रूसी समर्थन रूस ने हाल के वर्षों में तालिबान के साथ संबंध विकसित किये हैं। तालिबान के साथ किसी भी तरह की प्रत्यक्ष संलग्नता के लिये भारत को रूस के समर्थन की आवश्यकता होगी। ईरान का महत्त्वरू ईरान अफगानिस्तान के साथ एक लंबी भूमि–सीमा साझा करता है और उसके जातीय अल्पसंख्यकों से सांस्कृतिक संबंध रखता है। ईरान में भारत की चाबहार परियोजना का मूल उद्देश्य पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान तक प्रत्यक्ष पहुँच कायम करना था। अफगानिस्तान तक बड़ी मात्रा में आपूर्ति, गृहयुद्ध अथवा तालिबान द्वारा बलपूर्वक सत्ता अधिग्रहण की स्थिति में भी अपनी उपस्थिति मज़बूत बनाए रखने हेतु सभी परिदृश्यों में अफगानिस्तान तक प्रत्यक्ष पहुँच भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि भारत पर अमेरिका का दबाव दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों के मार्ग में एक बाधा है। चीन के साथ सहयोगरू अफगानिस्तान में एक राजनैतिक समाधान की तलाश और चिरकालिक स्थिरता के लिये भारत को चीन से भी संवाद करना चाहिये।

नई विकास भागीदारी

रणनीतिक भागीदारी के रूप में द्विपक्षीय विकास सहयोग को मान्यता प्रदान करते हुए तथा अफगानिस्तान में सामाजिक, आर्थिक, अधोसंरचना और मानव संसाधन विकास के लिए भारत द्वारा अफगानिस्तान को प्रदान की गई 2 बिलियन यूएस डॉलर की विकास और आर्थिक सहायता के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं के सकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष एक महत्वाकांक्षी तथा अग्रदर्शी अगली पीढी की नई विकास भागीदारी आरंभ करने पर सहमत हुए। इस संदर्भ में, सरकार तथा अफगानिस्तान के लोगों की प्राथमिकताओं और अनुरोध के अनुसार, दोनों पक्ष उच्च प्रभाव वाली 116 समुदाय विकास परियोजनाओं को आरंभ करने पर सहमत हुए जिन्हें अफगानिस्तान के 31 प्रांतों में क्रियान्वित किया जाएगा जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल, नवीकरणीय ऊर्जा, बाढ़ नियंत्रण, सूक्ष्म–जल विद्युत, खेल अधोसंरचना और प्रशासनिक अधोसंरचना के क्षेत्र भी शामिल हैं। भारत से सहायतानुदान के अंतर्गत निम्नलिखित नई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने पर भी सहमति हुईः

1. काबुल के लिए शहतूत बांध और पेयजल परियोजना जो सिंचाई में सहयोग प्रदान करेगी,
2. पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए नानगरहर प्रांत में अफगानिस्तान शरणार्थियो के लौटने के लिए कम लागत पर घरों का निर्माण,
3. बामयान प्रांत में बंद–ए–अमीर तक सड़क संयोजनता जो राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को आकर्षित करेगी और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी,
4. परवान प्रांत में चारिकार शहर के लिए जलापूर्ति नेटवर्क,
5. मूल्यवर्धित उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए काबुल में जिप्सम बोर्ड विनिर्माण संयंत्र की स्थापना,
6. मजार–ए–शरीफ में पॉलीटेक्नीक का निर्माण।

अफगानिस्तान पक्ष ने संचार अवसंरचना में विकास (आप्टिक फाइबर) तथा 180 मेगावाट क्षमता वाले सुरोबी 2 जलविद्युत संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया। भारतीय पक्ष ने इसका अन्वेषण करने पर सहमति प्रदान की। लोगों का लोगों के साथ संपर्क, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अफगान राष्ट्रिकों के लिए क्षमता निर्माण, कौशल और मानव संसाधन विकास हेतु व्यापक स्तर पर संचालित कार्यक्रमों का सकारात्मक रूप से आकलन किया गया। अफगान राष्ट्रिकों के लिए आईआईसीआर विशेष छात्रवृत्ति स्कीम की 10वीं वर्षगांठ को 2016 में मनाया गया था तथा इसे 2017 से 2022 तक की अवधि के लिए आगे और क्रियान्वित करने पर सहमति दी गई। यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों के शहीदों के बच्चों के लिए भारत में स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु 520 छात्रवृत्तियां आरंभ की जाएं तथा चिकित्सा सहायता को अफगान राष्ट्रीय सेना के कार्मिकों, तक विस्तारित कर दिया जाए। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) का प्रयोग राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला स्तरों पर अफगानिस्तान के प्रशासन और शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अफगानिस्तान की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाएगा जिसमें सिविल प्रशासन और परियोजना क्रियान्वयन की क्षमताओं का निर्माण करने के लिए अनुभवों की साझेदारी और तकनीकी सहायता का प्रयोग करना भी शामिल है। इस प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियां भी विकसित की जाएंगी। भारतीय विदेश सेवा संस्थान दिसम्बर, 2017 मे अफगान राजनयिकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करेगा जिसमें काउंसलर मामले भी शामिल हैं। कंधार में एएनएएसटीयू (अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) की स्थापना के संबंध में भारत की सहायता की सराहना करते हुए यह सहमति हुई कि एक कृषि विश्वविद्यालय के रूप में एएनएएसटीयू को मजबूत बनाने में और अधिक सहयोग को अन्वेषित किया जाएगा। मई, 2017 में प्रक्षेपित दक्षिण एशिया उपग्रह में अफगानिस्तान की प्रतिभागिता का स्वागत करते हुए भारत रिमोट सेंसिग प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में अफगानिस्तान की सहायता में वृद्धि करने के लिए सहमत हुआ। सांस्कृतिक तथा लोगों के लोगों के साथ संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए भारत–अफगानिस्तान फाउंडेशन के कार्य की सराहना करते हुए निकट भविष्य में भारत–अफगानिस्तान संस्कृति दिवस आयोजित करने के निर्णय का स्वागत किया गया। इसके अलावा, आईसीसीआर काबुल में अफगान राष्ट्रीय संगीत संस्थान को सहायता प्रदान करेगा जिसमें संगीत यंत्र भी शामिल हैं। पर्यटन तथा लोगों का लोगों के साथ संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों पक्षकार सांसदों, निर्वाचन आयोगों, मीडिया, महिलाओं युवाओं, धार्मिक नेताओं और संस्थाओं, खेल दलों के बीच विनिमय को और प्रोत्साहित करने तथा घनिष्ठ राष्ट्र/शहर संबंधों को सुकर बनाने पर सहमत हुए।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं अफगानिस्तान और भारत एक दूसरे के पड़ोस में स्थित दो प्रमुख दक्षिण एशिया देश हैं। दोनों दक्षिण एशियाई क्षेत्रिय सहयोग संगठन (दक्षेस) के भी सदस्य हैं। 21वीं सदी में तालिबान के पतन के बाद दोनों देशों के संबंध फिर से काफी मजबूत हो गए हैं। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में रचनात्मक हिस्सेदारी की है। चूँकि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के परिणामों के प्रभाव भारत पर भी पड़ेंगे अतः उसे अपने हितों की रक्षा और अफगानिस्तान की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये यूरेशियाई शक्तियों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। यदि भारत सक्रिय और धैर्यवान बना रहा तो नए अफगान चरण में उसके लिये अवसर के कई द्वार खुल सकते हैं। अभ्यास प्रश्नरू अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद भारत को अपने हितों की रक्षा और अफगानिस्तान की स्थिरता के लिये क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। तालिबान नेता का इशारा भारत और अफगानिस्तान के बीच हवाई गलियारे की ओर था जिसे पाकिस्तान द्वारा पारगमन की अनुमति देने से इनकार करने के मद्देनजर दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। स्तानिकजई ने भारत को इस क्षेत्र में एक ''महत्वपूर्ण देश'' बताया। स्तानिकजई ने कहा कि पाकिस्तान के जरिये भारत के साथ अफगानिस्तान का व्यापार ''बहुत महत्वपूर्ण'' है। स्तानिकजई ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा। तालिबान नेता ने अपने संबोधन में पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ अफगानिस्तान के संबंधों का भी जिक्र किया। स्तानिकजई ने कहा कि काबुल में ''समावेशी सरकार'' के गठन के बारे में तालिबान नेतृत्व और विभिन्न जातीय समूहों और राजनीतिक दलों के साथ विचार–विमर्श चल रहा है।तालिबान ने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद काबुल पर अपना शिकंजा कस लिया है. तालिबान लड़ाके इस समय काबुल से चंद क़दम दूर हैं। अफ़ग़ानिस्तान सरकार ने सैन्य बलों को पुनर्गठित करके काबुल की सुरक्षा का भरोसा दिया है लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि अफ़ग़ान सरकार बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगी। बाक़ी दुनिया के अलावा मुस्लिम देश भी अफ़ग़ानिस्तान के घटनाक्रम पर नज़र बनाए हैं. कुछ देशों की इस संकट में सक्रिय भूमिका है तो कुछ ने रणनीतिक ख़ामोशी यार कर ली है।

संदर्भ

1. पुखराज जैन, राजनीति विज्ञान, साहित्य भवन पब्लिकेषन आगरा, 2015।
2. सुधीर कुमार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेषन आगरा, 2014
3. प्रो. ममता चंद्रषेखर, भारत में राज्यों की राजनीति, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल 2020।
4. डॉ. गोविंद प्रसाद शर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल 2020।
5. डॉ. ममता चंद्रषेखर, प्रमुख देषों के संविधान, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल 2021।
6. डॉ. नलिनी रेवडीकर, उच्चतर राजनीतिक सिद्धांत, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल 2020।
7. डॉ. नलिनी रेवडीकर, भारतीय शासन एवं राजनीति, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल 2020।
8. डॉ. रामदेव भारद्वाज, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और समसामयिक राजनीतिक मुद्दे, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल 2020।
9. डॉ. ममता चंद्रषेखर, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल 2020।
10. इन्टरनेट का उपयोग।
11. प्रतियोगिता दर्पण माह अगस्त 2021।